



रा. रा. श्रीमान कमिशनर महोदय , राजस्व मण्डल इंदौर (म.प्र.)

PBR/नगरानी/धार/भू.सं/2017/3507

इस्लामुद्दीन पिता मुशी खा जाति मुसलमान  
आयु 55 वर्ष धन्धा काश्तकारी निवासी ग्राम  
सांभर तहसील व जिला धार (म.प्र.)

(2)

— अपीलान्ट

मि. प्र. कमिशनर  
19-08-17  
19-08-17

विरुद्ध

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर  
श्री प्र. प्र. अ. म. य.  
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 29-08-2017  
को प्रस्तुत।

- 1- श्रीमान सब-डिवीजनल ऑफिसर महोदय  
धार (म.प्र.)
- 2- श्रीमान तहसीलदार महोदय, धार (म.प्र.)
- 3- पटवारी ग्राम सांभर तहसील धार  
जिला धार (म.प्र.)

613

29-08-2017

अधीक्षक  
आयुक्त कार्यालय

— रिस्पोंडेंट

अपील अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा. संहिता 1959 विरुद्ध आदेश  
दिनांक

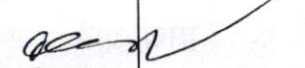
माननीय न्यायालय ,

अपीलान्ट के खिलाफ पटवारी हल्का नं 85 ग्राम सांभर तहसील व जिला धार के द्वारा धारा 248 म.प्र. ले.रे.कोड 1959 के अंतर्गत प्रतिवेदन अतिक्रमण बाबद तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार महोदय द्वारा एक पक्षीय आदेश के द्वारा उनके प्रकरण क्रमांक 208-अ-68/13-14 मे पारित आदेश दिनांक 15-08-2017 के द्वारा अपीलान्ट को 50,000/- रुपये अर्थ दण्ड का आदेश दिया जिसके खिलाफ श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय धार के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो प्रकरण क्रमांक 1/14-15-अ-68 मे पारित आदेश दिनांक 15-08-2017 के द्वारा स्थगन आवेदन निरस्त कर अपीलान्ट को 15

## न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्र

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/धार/भूरा/2017/3507

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-6-18	<p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। आवेदक द्वारा आलोच्य आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं कर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि से छूट हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। निगरानी में अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के कारण तहसील न्यायालय द्वारा म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के प्रकरण में आदेश पारित कर आवेदक पर रुपये 50,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। आवेदक के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में आवेदक को 15 दिवस के लिये सिविल जेल भेजने का आदेश दिया गया। जिसके विरुद्ध अपील अपर आयुक्त के यहाँ वर्तमान में लंबित है। अपर आयुक्त द्वारा स्थगन न देने के विरुद्ध यह निगरानी पेश की गई है। दोनों न्यायालयों के आदेश आवेदक के विरुद्ध होने से स्पष्ट है कि सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में नहीं है। आवेदक ने अपने निगरानी में प्रश्नाधीन भूमि शासकीय नहीं होकर उसके स्वत्व की है ऐसा कोई आधार नहीं लिया है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा स्थगन न देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।</p>	 <b>अध्यक्ष</b>

